सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 30 SEPTEMBER TO 6 OCTOBER 2020 • VOLUME- 10 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &

*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

*T&C apply

बाबरी विध्वंस केस: सभी 32 आरोपी बरी, स्पैशल कोर्ट के जज ने कहा – पूर्व नियोजित नहीं थी ढांचा गिराने की घटना

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अदालत ने सभी जीवित 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत का कहना था कि घटना अचानक हुई थी।

बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, महंत गोपालदास, विनय कटियार और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. जज एसके यादव ने कहा है कि विवादित ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और ये घटना अचानक हुई थी। अदालत ने सीबीआई के साक्ष्यों को नाकाफी करार देते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. ये केस बीते 28 साल से अदालत में लंबित था। आपको बता दें कि 6 दिसंबर, 1992 में हिंसक कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया था। 32 अभियुक्तों पर आरोप थे कि उन्होंने विवादित ढांचा को गिराने के लिए साजिश रची थी।

आज के फैसले के दौरान कोर्ट की टिप्पणी

- बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा का गिराया जाना पूर्व नियोजित नहीं था। अचाक गिराई गई।
- अभियुक्तों के खिलाफ नाकाफी सूबत हैं
- ऑडियो सबूत की सत्यता नहीं की जा सकती
- सीबीआई ने जो वीडियो सबूत के तौर पर पेश की, उसमें जो लोग गुंबद पर चढ़े थे, अराजक तत्व थे
- भाषण का ऑडियो क्लियर नहीं है

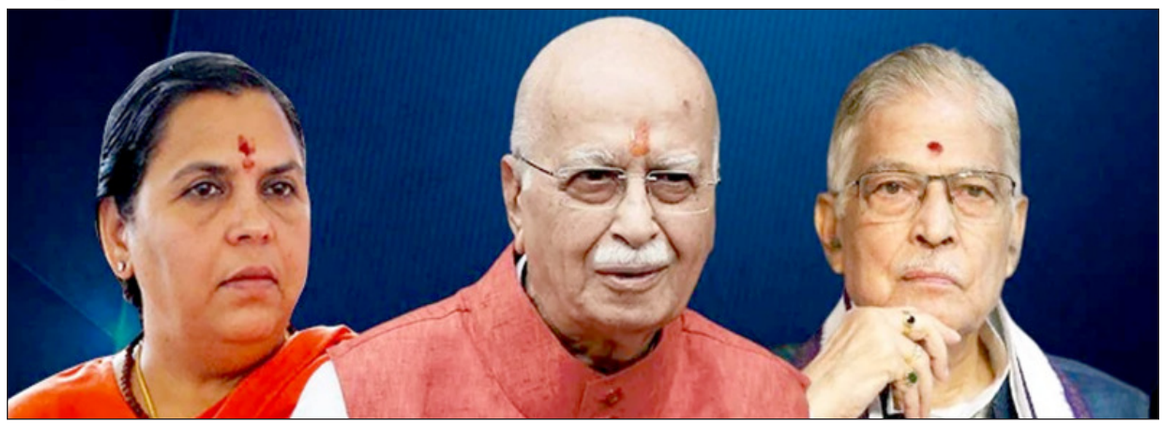

कोर्ट ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। ये घटना अचानक ही हुई थी, भीड़ ने ढांचे को गिरा दिया. कोर्ट ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहे अशोक सिंघल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं हैं। अदालत ने कहा कि भीड़ वहां पर अचानक से आई और भीड़ ने ही ढांचे को गिरा दिया. जिन 32 लोगों का नाम शामिल किया गया, उन्होंने भीड़ को काबू करने की कोशिश की। सिर्फ तस्वीरों के आधार पर ही किसी को दोषी नहीं बना सकते हैं। फैसले के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर लाल कृष्ण आडवाणी के वकील विमल श्रीवास्तव ने कहा, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, साक्ष्य इतने नहीं थे कि कोई आरोप साबित हो सके।

ये 32 बरी हुए

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती , महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी ऋतम्भरा, चम्पत राय, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, महंत धरम दास, पवन पांडेय, ब्रज भूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज,सतीश प्रधान, आरएन श्रीवास्तव, तत्कालीन डीएम, जय भगवान गोयल, रामचंद्र खत्री , सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, लल्लू सिंह, वर्तमान सांसद, ओम प्रकाश पांडेय, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र, रामजी गुप्ता।

बता दें कि अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी के विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने मामले में बाकी बचे सभी 32 मुख्य आरोपियों पर फैसला सुनाया।

बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट के फैसले पर ओवैसी नाराज, पूछा- क्या किसी जादू से मस्जिद ढह गई?

■ हैदराबाद/ब्यूरो

बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर देने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले पर क्षोभ जाहिर करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को इसे ''अप्रिय'' करार दिया और कहा कि केंद्रीय एजेंसी को इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए। अदालत ने मामले में दिया है। ओवैसी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए संवाददाताओं से कहा, ''फैसले से हिंदुत्व और उसके अनुयायियों की सामुहिक अंतरात्मा और विचारधारा को संतुष्टि मिलती है।''

उन्होंने पूछा, ''क्या छह दिसम्बर को किसी जादू से मस्जिद ढह गई? वहां लोगों को इकट्ठा होने के लिए किसने बुलाया? किसने सुनिश्चित किया कि वे वहां घुसें?'' ओवैसी ने कहा कि सीबीआई को फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए

सीबीआई अदालत के फैसले को ''अप्रिय'' करार देते हुए उन्होंने कहा कि वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इसके खिलाफ अपील करने का आग्रह करते हैं।

''ताकि उसकी स्वतंत्रता बची रहे।'' सीबीआई अदालत के फैसले को ''अप्रिय'' करार देते हुए उन्होंने कहा कि वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इसके खिलाफ अपील करने का आग्रह करते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 वीं जन्म शताब्दी पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन

■ जालंधर/रवि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 वीं जन्म शताब्दी के संदर्भ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं । इसी कड़ी में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा जालंधर के सूर्य एन्क्लेव स्थित केंद्रीय सदन परिसर में एक शानदार चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ।

ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित चित्रों को दर्शाया गया है। एक अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को चित्रों के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन पर जानकारी उपलब्ध करवाना है।

भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, मारक क्षमता 400 किमी से ज्यादा

■ बालासोर/ब्यूरो

भारत ने ओडिशा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बुधवार को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के सूत्रों ने बताया कि यहां पास में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) से अत्याधुनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया जो सफल रहा।

डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षण के दौरान सभी मानक प्राप्त कर लिए गए। प्रयोगिक परीक्षण पूर्वाह्न 10 बजकर 45 मिनट पर किया गया।

उन्होंने कहा कि मिसाइल को समुद्र, जमीन और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। मिसाइल के पहले विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण 11 मार्च 2017 को

किया गया था, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर थी।

तीस सितंबर 2019 को चांदीपुर स्थित आईटीआर से कम दूरी की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के जमीनी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया था।

डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एरोस्पेस उपक्रम एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्राह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है।

सूत्रों ने बताया कि यह मिसाइल पहले से ही भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के पास है।

इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है।

प्रोजेक्ट डायरैक्टर के जारी किये पत्र का नहीं हुआ कोई असर

जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

नैशनल हाईवे विभाग आगे दौड़ पीछा चौड़ की तरह काम कर रहा है विभाग दिन रात नए राष्ट्र राजमार्गों के ऐलान करके अपनी उपलब्धियों को गिनाते नहीं थकता परन्तु विभाग नव निर्माण राजमार्गों के रख-रखाव की और ध्यान देने की बजाये टोल वसूली में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है सुविधा के नाम पे लोगों को ठेंगा दिखता है और अपने गैर जिम्मेवार रवैये से लोगों की जान को मुश्किल में डालता है जिसका कारण जालंधर ब्रीज द्वारा अपने पिछले कई अंकों में हाईवे की त्रुटिओं के बारे में विभाग को जगाने का प्रयास किया गया जिस पर प्रोजेक्ट डायरैक्टर कालिया कॉलोनी ने तुरंत एक्शन

जालंधर ब्रीज के पिछले अंक में प्रकाशित की गई खबर

जालंधर ब्रीज में प्रकाशित खबर का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाईवे ने लिया कड़ा संज्ञान

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

पिछले कई अंकों में जालंधर ब्रीज द्वारा हाईवे में की गयी त्रुटियों को जनता के सामने उजागर किया गया जिस पर विभाग को तुरंत एक्शन लेकर उसको ठीक करवाना पड़ा उसी विस्तार में पिछले अंक में फगवाड़ा-रोपड़ हाईवे पर टोल के नजदीक आवारा पशुओं की समस्या को उजागर किया था और स्थानीय प्रशासन को कुम्भकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया था जिस पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट बलाचौर को पत्र लिख कर जालंधर ब्रीज की खबर का हवाला देते हुए इसे तुरंत हल करने के लिए लिखा और भविष्य में कोई जानमाल का नुक्सान ना हो सके इसके लिए अपनी पैट्रोलिंग टीम को भी चेताया।

पुडा विभाग/नैशनल हाईवे विभाग

आवारा पशुओं की दयनीय हालत के लिए कौन जिम्मेवार

जालंधर ब्रीज के पिछले अंक में प्रकाशित की गयी खबर।

लेते हुए सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट और हाईवे पैट्रोलिंग अधिकारियों को हाईवे पर आवारा पशुओं को हटाने के लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए लिखा परन्तु स्थिति वैसे की वैसे ही है सब कुछ कागजों में रह गया आवारा पशु आज भी टोल के नज़दीक हाईवे पर घूमते आपको नज़र आएंगे और स्थानीय निवासी अपने पशुओं को सड़क पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग कर रहे है जोकि बहुत बड़ी नालायकी अफसरों द्वारा दिखाकर लोगों की जान को मुश्किल में डालने का काम किया जा रहा है और संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे हुए है और इन्कंप्लीट हाईवे का सिर्फ टोल टैक्स वसूलने में व्यस्त है।

दखल

खत्म करना होगा चीन का बाजार

भारत और चीन के संबंधों में तनाव के बीच भारत ने कई चीनी एप्स को प्रतिबंधित कर चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाया है। इसका असर भी दिख रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। अगर भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बना लेता है और विदेशी कंपनियों को मौका देता है तो इस क्षेत्र में चीन को आसानी से टक्कर दी जा सकती है और वहां से होने वाले आयात को एकदम खत्म किया जा सकता है।

पिछले कुछ माह से पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो भी आर्थिक कदम उठाए हैं, उनका दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित है। यह इसलिए जरूरी हो गया कि भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है और यहां उसके आर्थिक हित भी कम नहीं हैं। उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर बड़ी परियोजनाओं तक में चीन की हिस्सेदारी है। इसलिए चीन को आर्थिक झटका देकर भी उसे काबू करने की रणनीति पर भारत तेजी से काम कर रहा है। इसी के तहत भारत ने चीन के कई सामान और ऐप प्रतिबंधित किए हैं और कई परियोजनाओं से उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। भारत के इन कदमों का कुछ असर तो अब दिखने भी लगा है। भारत में चीन से आयात में गिरावट आई है और दूसरी ओर चीन को होने वाला निर्यात बढ़ने लगा है।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष (2020) अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत में चीन से होने वाले आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29.20 फीसद की गिरावट आई है। चीन को आर्थिक चुनौती देने के लिए सरकार द्वारा टिक-टॉक सहित 224 चीनी एप पर प्रतिबंध, चीनी सामान के आयात पर नियंत्रण, चीनी सामान पर शुल्क बढ़ाने की रणनीति, देश में चीनी सामान का बहिष्कार, सरकारी विभागों में चीनी उत्पादों की जगह यथासंभव स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की प्रवृत्ति और लॉकडाउन में खरीद में कमी जैसे विभिन्न कारण चीन से आयात में बड़ी गिरावट की वजह रही हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है कि एक ओर जब चीन से भारत में आयात घट रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत से चीन को निर्यात बढ़ने लगा है। अप्रैल-जुलाई, 2020 के बीच भारत से चीन को होने वाले निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30.70 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

कोरोना आपदा के बाद अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने चीन से दूरियां बना ली हैं। जाहिर है, इसका असर चीन के साथ होने वाले व्यापार पर भी पड़ेगा। ऐसे में चीन ने भारत से अधिक मात्रा में कच्चे माल का आयात किया है। इससे यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त चीन से आयात घटने और निर्यात बढ़ने का जो परिदृश्य उभरा है, वह आगे भी बने रहने की संभावना है। चीन से आयात की जाने वाली कई वस्तुओं को भारत अगर अपने यहां बनाना शुरू कर देता है और उससे ज्यादातर चीजों का आयात बंद कर देता है तो भारत के लिए यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम तो होगा ही, चीन के लिए भी आर्थिक चुनौती बढ़ जाएगी। सरकार चीन से आयात की जाने वाली कई वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के हरसंभव प्रयास में जुटी है। यही वक्त की मांग भी है। जैसे खिलौना उद्योग को ही लें। वैश्विक खिलौना उद्योग करीब सात लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन भारत की इसमें हिस्सेदारी काफी कम है। ऐसे में खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देकर इसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

यह न सिर्फ चीन के लिए भारी नुकसान होगा, बल्कि भारत के लिए वैश्विक खिलौना कारोबार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा अवसर भी हो सकता है। स्थानीय स्तर पर खिलौना उद्योग बढ़ने से भारत छोटे उद्योगों को काफी मदद मिलेगी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से चीनी वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करते हुए देश में कुटीर और लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करके बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। ऐसे कई उत्पाद हैं जो बाहर से देश में आ जाते हैं और इसकी वजह से ईमानदार करदाताओं की ओर से व्यर्थ खर्च होता है। उनके विकल्प का निर्माण भारत में आसानी से किया जा सकता है और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

भारत के ऐसे कई मजबूत आर्थिक पक्ष हैं, जिनके आधार पर वह चीन को आसानी से आर्थिक रूप से पटखनी दे सकता है। इसके लिए भारत को वैश्विक निवेश, वैश्विक कारोबार और वैश्विक निर्यात बढ़ाने के उपाय करने होंगे। कोविड-19 के फैलाव के बाद चीन से काफी सारी विदेशी कंपनियों ने कारोबार समेटा है और इसका नतीजा यह हुआ कि चीन से भारी विदेशी निवेश निकल कर दूसरे देशों में जा रहा है। यह एक ऐसा अवसर है जब भारत चीन छोड़ कर जाने वाली विदेशी कंपनियों को अपने यहां अवसर दे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी को लेकर चीन के प्रति बनी नाराजगी से चीन में कार्यरत कई वैश्विक कंपनियां अपनी निर्माण इकाइयों को पूरी तरह या आंशिक रूप से चीन से बाहर स्थानांतरित करने की तैयारी में हैं। ऐसी कंपनियों जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, ई-कॉमर्स, वाहन, फूड प्रोसेसिंग और कपड़ा क्षेत्रों की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कारोबार को भारत में स्थानांतरित करने में रुचि दिखाई है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं हैं। अगर भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बना लेता है और विदेशी कंपनियों को मौका देता है तो इस क्षेत्र में चीन को आसानी से टक्कर दी जा सकती है और वहां से होने वाले आयात को एकदम खत्म किया जा सकता है।

भारत ने विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति के तौर पर पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, इस समय सरकार देश के विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आने वाले रसायनों के आयात को कम करने के लिए देश में ही उनके उत्पादन की तैयारी कर रही है और इसके लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेटिव- पीएलआइ) शुरू की गई है। इसके तहत आगामी पांच वर्षों में पच्चीस हजार करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। अभी भारत अपने दवा उद्योग, कीटनाशक और कुछ अन्य प्रमुख उद्योगों में उपयोग में आने वाले करीब अस्सी से नब्बे फीसद रसायन चीन से ही खरीदता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ा कर हम स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक ले जा सकते हैं। हम पेट्रोलियम उत्पाद, गूगल, फेसबुक जैसी सूचना तकनीक कंपनियों को छोड़ दें, तो अधिकांश क्षेत्रों में हमारे स्थानीय उत्पाद वैश्विक बनने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। इस समय दुनिया में दवाओं सहित कृषि, प्रसंस्करित खाद्य, वस्त्र और परिधान, ज्वेलरी, चमड़ा और चमड़े का सामान, कालीन और मशीनें व कलपुर्जे जैसी कई वस्तुओं की भारी मांग है। ऐसे में इन क्षेत्रों में भारत अपना बड़ा बाजार बना सकता है।

देश में जिन उद्योगों का उत्पादन बहुत कुछ आयातित कच्चे माल और आयातित वस्तुओं पर निर्भर है, उनके कच्चे माल के उत्पादन के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी, ताकि जरूरी कच्चा माल भी भारत में ही तैयार किया जा सके। इसके अलावा आत्मनिर्भरता के रास्ते में एक बड़ी चुनौती देश में आपूर्ति शृंखला सेवाओं को आसान बनाने और इसके लिए नए उपयुक्त बुनियादी ढांचे से भी संबंधित है। अगर भारत चीन से आयात होने वाले कच्चे माल में से आधा भी अपने यहां तैयार करना शुरू कर देता है, तो यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। चीन के साथ संबंधों में जिस तरह का उतार-चढ़ाव आ रहा है और यह भी साफ है कि उसकी पूरी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है, ऐसे में भारत को जल्द चीन पर से निर्भरता खत्म करनी होगी।

विचार

पाक को फिर लगा झटका

सार्क अध्यक्ष नेपाल की समिट बुलाने की मंशा को मालदीव ने फिर झटका दिया है। मालदीव ने साल की शुरुआत में भी अड़ंगा लगाया था। पाकिस्तान 2016 से अपने यहां सार्क समिट कराने की तैयारी किए है, मगर भारत के रुख के आगे उसकी चल नहीं रही है।

मालदीव ने फिर इस बात पर मुहर लगाई है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। साल की शुरुआत में मालदीव ने ओआईसी में भारत का साथ दिया था लेकिन अब सार्क देशों की बैठक को लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मालदीव ने पाकिस्तान में होने वाले 19वें सार्क समिट पर एक बार फिर रोक लगा दी है। सार्क विदेश मंत्रियो की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर सार्क समिट शुरू करने की बात कही थी। ये समिट 2016 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी थी लेकिन किसी ना किसी कारण से इसे टाला जा रहा था। अब एक बार फिर मालदीव की ओर से इस समिट को टाल दिया गया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि अभी पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है, इसलिए ऐसे समय में समिट पर चर्चा करना सही समय नहीं है। सार्क अध्यक्ष नेपाल ने समिट की प्रक्रिया करने की बात कही थी लेकिन मालदीव के हस्तक्षेप के बाद इसे टाल दिया गया।

ऐसा पहली बार नहीं है जब मालदीव ने भारत की इस तरह सहायता की हो। मई में ओआईसी की बैठक में, मालदीव ने ऐसे किसी एक्शन का समर्थन करने से मना कर दिया था जिसमे इस्लामोफोबिया के लिए भारत को बाहर कर दिया था। वहीं साल 2016 से पाकिस्तान इस्लामाबाद में सार्क समिट कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। पाकिस्तान 2016 से सार्क समिट होस्ट करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, 2016 के बाद भारत ने उरी, पठानकोट और पुलवामा के आतंकी हमले के बाद इवेंट का बहिष्कार करने का फैसला किया था। भारत ने कहा है कि समिट होने के लिए पाकिस्तान को ऐसा माहौल बनाना बड़ेगा। यही बात मालदीव ने भी दोहराई है। सार्क सम्मेलन स्थगित हो जाने से पाकिस्तान की समझ में आ गया होगा कि आतंकवाद पर उसका खेल अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। दुनिया के सामने उसकी पोल खुल चुकी है और अब भी उसने अपना रवैया नहीं बदला तो एकदम अकेला पड़ जाएगा।

उरी हमले के बाद पाक को अलग-थलग करने की भारतीय रणनीति रंग लाती दिख रही है। तब भारत ने साफ कर दिया था कि इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन की बैठक में वह हिस्सा नहीं लेगा। इस घोषणा का मकसद पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि हम उससे किसी भी तरह का संबंध तभी रखेंगे, जब वह आतंकी ढांचों को पालने-पोसने की नीति से बाज आएगा। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी भारत का साथ देते हुए सम्मेलन में शामिल न होने का निर्णय किया। सार्क का लगातार बहिष्कार करके भारत ने दुनिया को जता दिया है कि क्षेत्र विशेष को जोड़कर रखने वाला अकेला तत्व उसका भूगोल नहीं होता। दूसरी चीजें उसकी एकता के लिए ज्यादा मायने रखती हैं। पाकिस्तान जैसा देश लगातार समस्या खड़ी करता रहे तो यह ठीक नहीं है।

बचाना होगा छोटे उद्योगों को

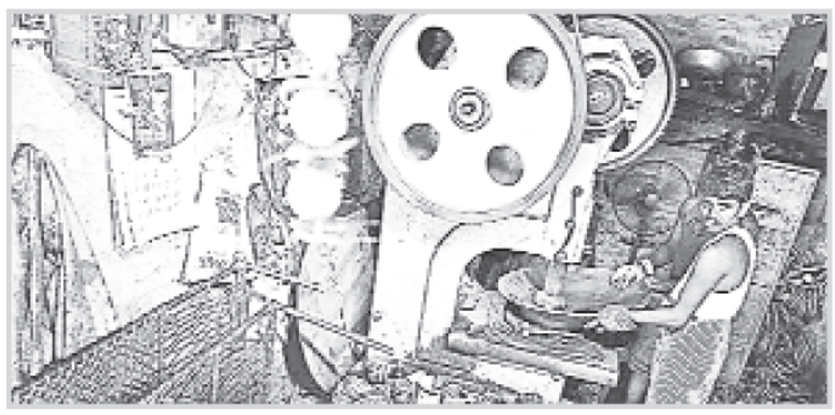

भारत की अर्थव्यवस्था को नोटबंदी और जीएसटी सुधारों के कारण भारी झटके झेलने पड़े हैं। इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। अब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए घोषित जीडीपी की दर हतोत्साहित करने वाली है। लॉकडाउनन के दौरान रोजगार गंवा चुके लोगों को फिर से काम-धंधा मल सके। यह समय अर्थव्यवस्था में सुधारों और राहत प्रदान करने का है।

रूस में लगभग 36 हजार और अमेरिका में बीस हजार गांव-शहर हैं। भारत में नगरों की बात छोड़ दें, तो अकेले गांवों की संख्या ही छह लाख से ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है। भारत गांवों और खेती-किसानी का देश है और यही बात भारत को शेष विश्व से अलग करती है। कुछ सिद्धांत सनातन होने के कारण अपरिवर्तनीय होते हैं और कुछ काल, स्थान, खंड, परिस्थिति और पारिस्थितिकी के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए जो सिद्धांत पूरे संसार में लागू होते हैं, वे ग्राम्य संख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत पर भी लागू हों, यह कहना उचित नहीं होगा। जब हम भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की चर्चा करते हैं, तो गुलाम मानसिकता के कारण तुरंत पश्चिम के विकास मॉडल की ओर ताकने लगते हैं, जिसे भारत में नेहरूवियन मॉडल कहा जाता है। यह कतई आवश्यक नहीं है कि विकास का जो सिद्धांत यूरोप और अमेरिका में सफल कहा जाता है, वह भारत पर भी लागू हो सकता है।

हालांकि पश्चिम में अब तक भी यह चर्चा जारी है कि विकास का जो मॉडल वहां अपनाया है, वह मॉडल क्या सचमुच प्रकृति के सभी अर्थों में सफल भी है या नहीं। यूरोप व अमेरिका के विकास में सर्वजन की भागीदारी पर प्रश्नचिन्ह होने के कारण अंतर्द्वंद्व और अंतर्कलह निरंतर हैं। फिर भी उस मॉडल को यदि सफल मान लिया जाए, तो भी यह विचारणीय है कि भारत के संदर्भ में उसकी उपादेयता है या नहीं। भारत के विकास के साथ यहां के 6.38 लाख गांवों के लगभग अस्सी करोड़ लोगों के जीवन-यापन का प्रश्न जुड़ा हुआ है। यूरोप में यांत्रिकीकरण का सिद्धांत उचित जान पड़ता है। वहां प्रति व्यक्ति संसाधन अधिक हैं और काम करने वाले हाथ कम हैं। इसलिए मशीनों की सहायता से अधिकाधिक उत्पादन कर श्रम लागत कम रखना उनका उद्देश्य हो सकता है। किंतु पहले तो बड़े कारखानों को बढ़ावा देना और फिर श्रम लागत कम करने के लिए मशीनीकरण को श्रेयस्कर मानना भारतीयों के लिए बड़ी भूल सिद्ध हुई है। इससे बेरोजगारी बढ़ी है। पश्चिमी सोच वाली नीतियों का ही परिणाम है कि आज भारत में खेती-किसानी घाटे का स्थापित सत्य हो गई है। खेतिहार मजदूर, किसान अब कृषि छोड़ बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। कारण कि पश्चिम के विकास मॉडल के चलते हमारी कृषि आत्महत्या की खेती हो गई है। पश्चिम देशों के इसी मॉडल के चलते बेतरतीब शहरीकरण की समस्या भी बढ़ी है।

दुनिया की दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाले भारत में विशालकाय अर्थव्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया जाता है। उसके महत्व को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। सबसे पहले सूक्ष्म अर्थव्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है, जिसका सीधा संबंध बाजार खंड और उससे जुड़े आमजन से होता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का सपाट अर्थ है कि विभिन्न बाजार खंडों के उद्योग-धंधों के माध्यम से व्यक्तियों को जोड़ कर रोजगार और स्वरोजगार का सृजन करना। जब देश की सूक्ष्म अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, तो विशाल अर्थव्यवस्था के मौद्रिक नीति, जीडीपी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, गरीबी आदि बिंदुओं का समेकित आकलन और व्यवस्था अपने आप ही सहज और सरल हो जाएगी। भारतीय समृद्धि का आधार हमारे कुटीर और ग्रामोद्योग ही हो सकते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, 'अगर गांव नष्ट हो जाएं, तो हिंदुस्तान भी नष्ट हो जाएगा।

आज शहर गांवों की सारी संपत्ति खरीद लेते हैं। इससे गांवों का नाश हो रहा है। ग्रामीण कर्ज के बोझ से दबे हैं। मैं जिस देहात की कल्पना करता हूं, वह देहात जड़ नहीं होगा। वह शुद्ध चैतन्य होगा।' अंग्रेजों से पहले तक कुटीर उद्योगों के बूते भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत की साख आज के वाशिंगटन, मास्को, लंदन और पेरिस से कहीं ज्यादा थी। तब विदेशी भारत के विकास की गौरवगाथाएं सुन कर खिंचे चले आते थे। कुटीर उद्योगों पर सबसे बड़ा प्रहार अंग्रेजों के समय में ही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा, चाय यहां तक कि नमक जैसी चीजों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने का भी अधिकार नहीं था और इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए तो भारतीयों को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। तब 1930 में गांधी जी को नमक आंदोलन भी करना पड़ा था।

अंग्रेज अपने हित के लिए बड़े कारखानों की संकल्पना लेकर आए, जिसमें कपड़ों की बड़ी मिलें लगाई गईं और जूतों के बड़े कारखाने लगाए गए। इससे हमारे शताब्दियों से चले आ रहे कपड़े और जूते जैसे व्यवसाय ठप हो गए। अब जो हाल है, उसमें परिवार बढ़ने से जमीनों का बंटवारा हो गया और एक एकड़ से भी कम जमीन के किसानों की संख्या बढ़ गई है। उस जमीन से परिवार का पोषण असंभव हो गया है। परचून की दुकानों की जगह विशालकाय मॉल तक आ गए हैं। चमड़ा शोधन इकाइयां और उत्पाद गांव से निकल कर टेनरियों और जूता कंपनियों के अधीन हो गए हैं। कपड़ा उद्योग में कपास की कताई, बुनाई और सिलाई जैसे काम बड़ी मशीनों से होने लगे हैं। एक ओर किसान गुस्से में आलू-प्याज सड़कों पर फेंकते नजर आते हैं, तो कई स्थानों पर ये महंगे दामों पर बिक रहे होते हैं। वितरण प्रणाली हाशिए पर आ गई है। कुटीर उद्योग लगभग ठप हो गए हैं। कृषि यंत्र कभी गांव का लुहार गढ़ता था। अब खुर्पियां व फावड़े मशीनों से बनने लगे हैं, यहां तक कि चीन से आयात करते हैं। हम खरबों रुपए की विदेशी मुद्रा चीन में निर्मित मोबाइल फोनों पर गवां रहे हैं।

प्रतिकार में चीन हमारा खाकर गलवान और पैंगोंग में हम पर ही गुरानें का दुस्साहस कर रहा है। हम आईसीबीएम और ड्यू की ओर तो बढ़ रहे हैं। किंतु हम मोबाइल फोन बनाने का नवाचार नहीं दिखा पाए। लीथियम बैटरी के अभाव में हमारा सौर ऊर्जा का कार्यक्रम पंगु बना हुआ है। ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं। सारांश यह है कि नवाचार के साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अंतर पाटने की आवश्यकता है। विशाल अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विश्व व्यापार परिदृश्य, भूमंडलीकरण, विश्व समझौतों के दृष्टिकोण से बड़े उद्योगों की उपयोगिता, विवशता को अब नकारा तो नहीं जा सकता है। लेकिन बड़े उद्योगों की आपूर्ति शृंखला में लघु और कुटीर उद्योगों को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ समाहित अवश्य किया जा सकता है। किंतु यह सावधानी रखनी होगी कि बड़े उद्योगों का विकास लघु व कुटीर उद्योगों की कीमत पर न हो, ताकि रोजगार के अवसर अधिकाधिक सृजित हो सकें। कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। छोटी जोत के किसानों के लिए डेयरी पालन, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण के प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। अब उन्हें व्यापक फलक की आवश्यकता है।

अब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए घोषित जीडीपी की दर हतोत्साहित करने वाली है। हालांकि अगली तिमाही में इसके सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और सभी रेटिंग एजेंसियां 2021-22 में जीडीपी दस प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना बता रही हैं। किंतु वर्तमान स्थिति में अर्थव्यवस्था को गति के लिए आवश्यक है कि सरकार ऐसे उपाय करे कि मांग में तेजी आए।

ट्विटर

हमारा एजेंडा स्पष्ट है। पाक जब तक आतंक को प्रश्रय देता रहेगा हम उससे बात नहीं करेंगे। वह आतंक का रास्ता छोड़े, तो हम कहीं भी उससे बात कर सकते हैं।

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री

आतंक के माहौल में भारत का सार्क समिट से किनारा सही है। पाक को समझना चाहिए कि संबंध बनाने से बनते हैं। जैसा मालदीव कर रहा है। पाक अपनी आतंक की नीति छोड़े।

कमर आगा, रक्षा विशेषज्ञ

सत्यार्थ

मन पर नियंत्रण जरूरी

यह प्रसिद्ध समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के बचपन की बात है। तब रानाडे बंबई में रहते थे। उनके पड़ौस में ही एक महिला रहती थी, जो एक संपन्न घराने की थी, पर भाग्य का चक्र ऐसा घूमा कि अब उसके पास धन नहीं रह गया था। उसको बस इतनी आय हो जाती थी कि वह अपना और इकलौते बेटे का किसी तरह पेट भर सके। फिर भी वह महिला दुखी रहती और अकेले में बैठकर रोया करती। एक दिन बालक रानाडे ने उसको रोते हुए देखा तो उसके दुख का कारण पूछा। महिला ने उन्हें अपने पुराने दिनों का वैभव सुनाते हुए कहा-हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर अब ऐसा नहीं है। मेरे दुख का कारण वास्तव में मेरी जीभ का चटोरापन है। पहले हमारे घर में नाना प्रकार के व्यंजन पका करते थे और मैं उनका खूब आनंद उठाती थी। स्वाद के चक्कर में मैं अपनी सेहत की परवाह भी नहीं करती। इसका असर यह हुआ कि मैं बीमार रहने लगी। मुझे खूब दवाएं लेनी पड़ती थीं। यह कह कर महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली- मगर अब जब से वे चीजें खाने को नहीं मिलतीं, मैं स्वस्थ रहने लगी हूं। अब मुझे किसी भी औषधि को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने मन को बहुत समझाती हूं कि नाना प्रकार के व्यंजनों के दिन गए, अब उनका स्मरण करने से भी कोई लाभ नहीं है। फिर भी जीभ नहीं मानती। बेटा तो रूखी-सूखी खाकर पेट भर लेता है व खुश रहता है। उसने वे दिन नहीं देखे। उस महिला की दशा देख रानाडे ने उसी पल तय कर लिया कि जीभ जिस पदार्थ को ज्यादा पसंद करे, उसका सीमित मात्रा में सेवन करेंगे और जीभ के गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने इस व्रत को आजीवन निभाया।

कुशवाहा ने बीएसपी-जेपीएस संग बनाया नया मोर्चा

पटना, (एजेंसी)। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के बाद एनडीए से भी बात नहीं बन पाई। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाया।

इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी और नीतीश सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए बिहार की जनता को अब एक नए विकल्प की आवश्यकता है। उपेंद्र ने कहा कि पिछले 30 सालों से बिहार में जंगलराज कायम है। कुशवाहा ने कहा कि 15 साल पहले और आज के 15 साल वाले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुशवाहा ने इशारों-इशारों में तेजस्वी पर बड़ा अटैक किया है। कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन में भी भाजपा का दखल है। कुशवाहा का कहना है कि ऐसी चर्चा है कि किसी न किसी रूप में भाजपा महागठबंधन में भी अपनी पकड़ रखती है।

फेल स्टूडेंट से प्रतियोगिता करना चाहते हैं नीतीश कुमार: उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार 15 साल पहले की चर्चा करते हैं, अपने काम का नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि लालू राज से तुलना कर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, नीतीश कुमार। कुशवाहा ने महागठबंधन को फेल बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार फेल स्टूडेंट से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा दो-तीन दिन के दिल्ली प्रवास के बाद सोमवार को पटना पहुंचे। महागठबंधन से दूरियां बढ़ने के बाद एनडीए के अलावा वे अब तीसरे मोर्चे की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं।

एनडीए में रार जारी, एलजेपी ने कहा- चिराग हमारी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार

पटना, (एजेंसी)। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर-शोर पर हैं। एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार हैं तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं, एलजेपी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान निश्चित रूप से हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जेडीयू और भाजपा बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एनडीए के दो सबसे बड़े दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा अपने अंतिम दौर में हैं।

अभियान

नई दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के एक कर्मचारी ने यमराज के भेष में मंगलवार को 'मास्क या यमराज' अभियान के दौरान कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑटोरिक्शा चालकों को मास्क पहनने की सलाह दी।

न्यूज

अंतराष्ट्रीय हस्तियों ने जसवंत सिंह के निधन पर जताया शोक

बाड़मेर, (एजेंसी)। बौद्ध धर्म गुरु दलाईलामा सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लौटी टी शेरिंग ने पुत्र मानवेन्द्र सिंह को पत्र भेजकर सिंह को महान व्यक्तित्व का धनी बताते शोक संवेदना प्रकट की, वहीं भूटान के चौथे महाराज जिग्मे सिंधे वांगचुंक ने शोक संवेदना व्यक्त की। भूटान सरकार के भारत मे राजदूत वी नामगेल ने भी संवेदना जताई। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एफ डेब्यू डी ई क्लर्क ने लिखा कि जसवंत सिंह असाधारण अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों में शुमार रहे।

पाक ने पैदल यात्रियों के लिए अफगानिस्तान बार्डर खोली

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। पाकिस्तान ने मंगलवार को अफगानिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लगने वाली बॉर्डर पैदल यात्रियों के लिए खोल दी, जो मार्च में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बंद कर दी गई थी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार के पी प्रांत में सभी बॉर्डर टर्मिनल पैदल यात्रियों के लिए सप्ताह में चार दिन यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को खुले रहेंगे। अधिसूचना में बताया गया कि तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान आ रहे लोगों के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा जरूरी होगा। पाक ने पहले ही दक्षिण-पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में पैदल यात्रियों के लिए अफगानिस्तान के साथ स्थित चमन सीमा को खोल दिया है।

अफगानिस्तान में बम विस्फोट में 11 लोगों की मौत

काबुल, (एजेंसी)। अफगानिस्तान के मध्यवर्ती प्रांत डेकुंडी में मंगलवार को बम विस्फोट में कम से कम 11 नागरिकों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रमुख गुलाम सखी गफूरी ने बताया कि कुजरान जिले के दश्त-ए-सुलेमान इलाके में 17 लोगों को ले जा रहा एक वाहन स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजे एक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण (आईईडी) से टकरा गया। विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। श्री गफूरी ने बताया कि वाहन में सवार लोग जिले के आसपास के इलाकों में तीर्थयात्रा के लिए गए थे। उन्होंने हमले के लिए आतंकवादी संगठन तालिबान को जिम्मेदार ठहराया।

कैलिफोर्निया के जंगल में फैली आग से तीन की मौत

सेन फ्रांसिस्को, (एजेंसी)। अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत में जंगल से फैली भीषण आग की चपेट में आकर कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों को उनके घरों से निकालकर बचा लिया गया। यूएसए टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक शास्ता काउंटी के शेरिफ एरिक मगरिनी ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी है। कैलिफोर्निया के वन एवं अग्निशमन विभाग ने बताया कि रेडिंग के पास 31,200 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया है जबकि नापा और सोनोमा काउंटी में 36,200 एकड़ इलाके में आग फैली है।

भारत से मनमुटाव के बीच जनगणना की तैयारी कर रहा नेपाल

सिद्धार्थनगर (बड़नी), (एजेंसी)। नेपाल की केपी ओली सरकार विवादित लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों में जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। नेपाल की राष्ट्रीय योजना आयोग और केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने अगले साल 28 मई से होने वाली 12वीं राष्ट्रीय जनसंख्या और आवास जनगणना में इन विवादित क्षेत्र को शामिल करने की योजना तैयार की है।

जनगणना से पूर्व लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण कराने की तैयारी की जा रही है। ओली सरकार ने चालीस हजार से अधिक प्रगणक और नौ हजार पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। नेपाल में योजना आयोग के सदस्य मिन बहादुर शाही ने बताया कि आयोग कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा में जनगणना की तैयारी कर रहा है। यदि यह संभव नहीं हुआ तो आयोग अन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है।

नेपाल ने छह दशक पहले लिपुलेख में आखिरी जनगणना की थी। सर्वेक्षण विभाग के पूर्व महानिदेशक बुद्ध नारायण श्रेष्ठ के अनुसार नेपाली पक्ष ने विवादित क्षेत्र कालापानी के व्यास नगर गांव विकास समिति (गाविस) के तीन गांव-कुंजी, नवी और कुटी में एक अनौपचारिक सर्वेक्षण कराया था और घरों और आबादी की संख्या दर्ज की थी। तब 150 घरों में 723 लोगों की आबादी दर्ज की गई थी। 1991 में भारतीय सुरक्षा बलों ने नेपाली प्रगणकों को कालापानी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रोक दी थी।

विदेशों से चंदा लेकर भारत के राजनीतिक मामलों में दखल की इजाजत नहीं

एमनेस्टी इंटरनेशल को जवाब देकर सरकार ने खोली पोल

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत सरकार की ओर से निशाना बनाए जाने और खातों को पूरी तरह फ्रीज करने का आरोप लगाते हुए देश में कामकाज रोकने की घोषणा करने वाले मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशल को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्रालय ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के रूख और उसके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, अतिरंजित और सच्चाई से दूर बताते हुए कहा है कि संस्था भारत में मानवतावादी कामों को जारी रखने के लिए आजाद है, लेकिन विदेशी चंदों के जरिए घरेलू राजनीतिक चर्चाओं में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाएगी।

गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार जारी बयान में कहा गया कि यह कानून एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित सभी संस्थाओं पर लागू होता है। मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की अवैध गतिविधियों की वजह से पिछली सरकारों ने भी विदेशों से चंदा लेने की उसकी अपीलों को खारिज कर दिया था। उस समय भी एमनेस्टी को एक बार भारत में अपने कामकाज को रोकना पड़ा था। गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) एक्ट के तहत केवल एक बार मंजूरी ली थी, वह भी 20 साल पहले। इसके बाद से संस्था को एफसीआरए अप्रूवल देने से सभी सरकारों ने इंकार किया है। एफसीआरए नियमों को दरकिनार करते हुए एमनेस्टी यूके ने भारत में रजिस्टर्ड 4 इकाइयों में बड़ी राशि ट्रांसफर की थी।

अनुसंधान कार्य रोकने के लिए मजबूर करने का आरोप

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में उसके खातों के फ्रीज होने से अपनी सभी गतिविधियों को रोक रहा है और दावा किया है कि उसको निराधार और प्रेरित आरोपों को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। संगठन को भारत में कर्मचारियों को निकालने और उसके जारी सभी अभियान और अनुसंधान कार्यों को रोकने के लिए मजबूर किया गया है।

संगठन बोला- बैंक खाते किए पूरी तरह से फ्रीज

संगठन ने कहा कि भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है, जिसके बारे में 10 सितंबर 2020 को पता चला था, इसलिए संगठन द्वारा किए जा रहे सभी कामों को रोक दिया गया है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि एमनेस्टी को अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में बैंगलुरू में एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय की तलाशी की थी। ये छापे विदेशी मुद्रा अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए किए गए थे।

एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा

संगठन ने दावा किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और अन्य मुखर मानवाधिकार संगठनों, कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों पर हमले केवल विभिन्न दमनकारी नीतियों और सत्य बोलने वालों पर सरकार द्वारा निरंतर हमले का विस्तार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार संगठनों पर निराधार और प्रेरित आरोपों को लेकर लगातार किए जा रहे हमलों की कड़ी में यह नई घटना है।

लेह के अलची इलाके में आया भूकंप, मापी गई 3.2 की तीव्रता

जम्मू, (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर से सटे लेह के अलची इलाके के पास मंगलवार दोपहर दो बजकर 38 मिनट पर 3.2 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार भूकंप आ रहा है।

इससे पहले सोमवार सुबह भी जम्मू-कश्मीर में रिक्टर पैमाने पर 4.2 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिसकी गहराई सतह से महज पांच किलोमीटर नीचे थी। इतना ही नहीं इससे पहले शनिवार को भी दोपहर के वक्त यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी द्वारा रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई थी। शनिवार से पहले गुरुवार को भी सुबह 08.19 बजे गुलमर्ग में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता से भूकंप आया था। इससे पहले मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के लिहाज से जम्मू-कश्मीर संवेदनशील इलाके में आता है। भूकंप से पूर्व में कई बार कश्मीर में तबाही आ चुकी है।

धरती हिलते ही घरों से बाहर निकले लोग

गुजरात के राजकोट में भी महसूस किए गए 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके

राजकोट, (एजेंसी)। गुजरात के राजकोट शहर में मंगलवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च (आईएसआर) की ओर से बताया गया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। आईएसआर के मुताबिक, भूकंप के झटके दोपहर तीन बजकर 49 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राजकोट जिले से 25 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में 14.5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। राजकोट में भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की वजह से कुछ घरों में दरारें आ जाने की भी सूचना है।

गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव का भारत ने किया विरोध, कहा

कब्जे वाले क्षेत्रों पर पाक का कोई अधिकार नहीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित गिलगित-बाल्टिस्तान में होने वाले चुनावों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। पाकिस्तान ने यहां विधानसभा चुनाव का एलान किया है, जो 15 नवंबर को होने जा रहा है। भारत का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने 15 नवंबर, 2020 को होने वाले तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा के बारे में रिपोर्ट देखी है। हम पाकिस्तान के इस कदम का कड़ा विरोध जताते हैं। बयान में कहा गया कि भारत इस बात को फिर से दोहराता है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ-साथ गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र 1947 से ही भारत का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान सरकार के पास अवैध रूप से और जबरन उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।

भारत ने किया हालिया कार्यों को खारिज

बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान (चुनाव और कार्यवाहक सरकार) संशोधन आदेश 2020 जैसे हालिया कार्यों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली इस्लामाबाद द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे के तहत क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयास का विरोध करता है। इसमें कहा गया, इस तरह की कार्रवाई न तो पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे को छिपा सकती है और न ही पिछले सात दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वतंत्रता के उल्लंघन और शोषण को।

अमेरिका 15 करोड़ त्वरित कोविड-19 जांच किट वितरित करेगा: ट्रंप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले हफ्तों में 15 करोड़ रैपिड कोविड-19 जांच किट वितरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से बंद चल रहे स्कूल और व्यवसायों के फिर से खुलने के मद्देनजर लिया गया है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पत्रकारों को बताया कि आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम आगामी हफ्तों में 15 करोड़ त्वरित जांच किट वितरित करने की योजना की जल्द घोषणा करेंगे। यह संख्या अब तक हुई कुल जांच की संख्या से भी अधिक होगी। इनमें से 1.8 करोड़ जांच किट नर्सिंग होम, 1.5 करोड़ किट आश्रितों के लिए, एक करोड़ घरों, स्वास्थ्य सुविधाओं और धर्मशालाओं को और 10 लाख अश्वेतों की बहुलता वाले कॉलेज और विश्वविद्यालय, जनजातीय राष्ट्रीय कॉलेज सहित पांच करोड़ जांच किट सबसे अधिक प्रभावित समुदायों को दिए जाएंगे।

अमेरिका में कोरोना से अब तक दो लाख से ज्यादा लोगों की मौतें

ट्रंप ने कहा कि 10 करोड़ रैपिड पॉइंट-ऑफ-केयर जांच किट राज्यों और क्षेत्रों को व्यवसायों और स्कूलों को पुनः खोलने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दिया जाएगा। अमेरिका में अब तक दो लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 संक्रमण से जान जा चुकी है और 70 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।

एचएएल का 300वां एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जल्द लगाएगा आकाश में गोते

बेंगलुरू, (एजेंसी)। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने 300वें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का निर्माण पूरा कर लिया है। कंपनी ने मंगलवार को इसे अपने हैंगर से रोल आउट कर दिया है। रोल आउट होने के बाद यह अब आकाश में गोते लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी के सीएमडी आर माधवन ने कहा कि एएलएच मार्क- I से मार्क- IV तक का विकास अभूतपूर्व रहा है और यह हेलीकॉप्टरों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को प्रोत्साहन देता है। स्वदेशी ध्रुव ने पहली बार 1992 में उड़ान भरी थी। उसके बाद से भारतीय सेना के लिए हर स्तर पर मददगार साबित हुई।

बीजिंग में नेपाल के राजदूत बन गए चीनी तोता

काठमांडू, (एजेंसी)। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा अप्रैल के अंत में अचानक चीन के राजदूत बनाए गए महेंद्र बहादुर पांडे चीनी तोता बन गए हैं। चीन के साथ बेहतर रिश्ते बनाने बीजिंग भेजे गए राजदूत ड्रैगन के प्रवक्ता के रूप में काम करने लगे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जिस तरह उन्होंने एक तरफ चीन की जमकर तारीफ की तो भारत पर नेपाली जमीन कब्जाने सहित कई गंभीर और झूठे आरोप मढ़ डाले। पांडे के इस इंटरव्यू से खुद

नेपाल के जानकार और विश्लेषक हैरान हैं और उनकी कूटनीतिक समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

चीन के सरकारी अखबार को दिए इंटरव्यू में महेंद्र बहादुर पांडे ने चीन-नेपाल रिश्तों की तारीफ की और कहा कि भारत के साथ भारतीय और विदेशी मीडिया चीन-नेपाल रिश्तों को खराब करने की कोशिश में है। केपी ओली सरकार ने अप्रैल में अचानक लीलामणी पौडयाल को बीजिंग से वापस बुलाकर पांडे को भेज दिया था। इस बदलाव को लेकर अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया है। काठमांडू पोस्ट की एक खबर के मुताबिक, महेंद्र बहादुर पांडे के इस इंटरव्यू की नेपाल में तीखी आलोचना हो रही है। विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों के नेताओं ने पांडे के बयानों को गैरकूटनीतिक एक राजदूत के दायरे से बाहर बताया है, जो कि प्रोटोकॉल के उल्लंघन वाला है।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

अपराध

परिवहन विभाग की जांच में हुआ जालसाजी का खुलासा

गलत नंबरों से दौड़ रहे 11 हजार से ज्यादा ट्रक

कानपुर, (एजेंसी)। पहले कानून का उल्लंघन फिर कार्रवाई से बचने के लिए जालसाजी का अपराध। इसका खुलासा परिवहन विभाग की जांच में हुआ है। कानपुर-हमीरपुर मार्ग के अलियापुर टोल प्लाजा से गुजरने वाले 11 हजार से ज्यादा ट्रकों पर फर्जी नंबर प्लेट पाई गई है। टोल प्रबंधन ने ओवरलोड ट्रकों का जो डेटा विभाग को भेजा था, उसके आधार पर हुई कार्रवाई में यह जालसाजी उजागर हुई है।

बुंदेलखंड से मध्य उप्र को गिट्टी-मुरम की बंपर से ढुलाई होती है। हजारों ट्रक निर्धारित मानक से डेढ़ गुना तक भार लाद कर हाईवे पर निकलते हैं। इससे साधारण सड़कें ही नहीं राजमार्ग भी टूट रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने परिवहन विभाग को इसकी रोकथाम के लिए कहा था। ट्रिब्यूनल का आदेश था कि कानपुर सहित सूबे के पांच जिलों में टोल प्लाजा से निकलने वाले ओवरलोड वाहनों का रिकार्ड पर लेकर उनके ई-चालान किए जाएं।

कार्रवाई शुरू हुई तो यूं खुला खेल: परिवहन विभाग ने अलियापुर टोल प्लाजा से 23 जून से 20 अगस्त के बीच वहां से गुजरे ओवरलोड ट्रकों की सूची मांग ली। टोल प्लाजा पर वेइंग इन मोशन मशीनें लगी हैं। इनमें सारा डेटा भी फीड है। ट्रक गुजरते ही उस पर दर्ज नंबर, ट्रक की क्षमता और कितनी ओवरलोडिंग है, यह सब रिकार्ड हो

जाता है। टोल ने 59 दिन में 61,992 ओवरलोड ट्रकों के गुजरने की सूचना परिवहन विभाग को उनके नंबरों और फोटो सहित दी। इस सूची पर परिवहन के प्रवर्तन दस्ते ने ई-चालान शुरू किए। कुछ दिन में ही विभाग ने 1798 चालान कर डाले। खुलासा तब हुआ जब चालान का मैसेज पाकर लोग विभाग में पहुंचने लगे। गोविंदनगर निवासी सुनील शर्मा चालान खत्म कराने को लेकर आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं।

चालान के पहले वाहन नंबर का ब्योरा निकाल रहे

ट्रक के नाम पर कार-डंपर के चालान से हड़कंप मचा। विभाग ने जांच शुरू की तो पता चला कि 11,090 ट्रकों के नंबर ही फर्जी थे। हार कर महकमे ने अब तक किए गए 1798 वाहनों के चालान खत्म कर दिए हैं। एआरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त यादव ने बताया कि अब चालान के पहले वाहन नंबर का ब्योरा निकाल रहे हैं। जब वाहन के ट्रक होने की तस्दीक हो जाती है, तभी ई-चालान कर रहे हैं। डीके त्रिपाठी, अपर परिवहन आयुक्त, कानपुर कहते हैं कि ओवरलोडिंग का धंधा आखिरी सांसें गिन रहा है। कुछ जालसाज ट्रांसपोर्टर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धंधा चला रहे हैं। जांच में 11 हजार से ज्यादा फर्जी नंबरों पर चल रहे ट्रकों का पता चला है। यह जालसाजी भी जल्द बंद होगी।

कोरोना से मौत के मामलों में वृद्धि के बाद ब्रिटेन में सख्त पाबंदी

लंदन, (एजेंसी)। ब्रिटेन ने संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर सख्त पाबंदी लगाने की घोषणा की है। इंग्लैंड और वेल्स में लगातार दूसरे सप्ताह कोरोना संक्रमण से मौतों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) ने पाया है कि इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से में संक्रमण से मौत के मामले बढ़ गए हैं। क्षेत्र में जमावड़े और लोगों के सामाजिक मेल-जोल के कार्यक्रमों पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है।

उत्तरी-पूर्वी इंग्लैंड के न्यूकैस्टल, नार्थअंबरलैंड, गेटशीड, नार्थ टायनेसाइड, साउथ टाइनेसाइड, सुंदरलैंड और काउंटी डरहम काउंसिल क्षेत्रों में सामाजिक मेल-जोल से लोगों को परहेज करने को कहा गया था, लेकिन मंगलवार से लागू कानूनों के तहत नियमों का पालन नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। पहले अपराध पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 200 पाउंड का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार अपराध होने पर 400 पाउंड का जुर्माना लगेगा और बाद के अपराध पर यह बढ़ते हुए 6400 पाउंड तक हो जाएगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने नए सख्त प्रावधानों का हवाला देते हुए संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि दुर्भाग्य से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्र में प्रति लाख पर 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। ब्रिटेन में अब तक 42,000 लोगों की मौत हुई है। सरकार संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की नीति अपना रही है। संक्रमण की पुष्टि होने के बावजूद पृथक-वास के नियम नहीं मानने पर भी जुर्माना राशि 1,000 पाउंड से बढ़ाकर 10,000 पाउंड कर दी गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा बार, मैरिज पेलेस, होटल और रैस्टोरैंटों की सालाना लाइसेंस फीस और तिमाही अनुमानित फीस माफ करने को मंज़ूरी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के साथ सहमति प्रकट करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को बार, मैरिज पेलेस, होटल और रैस्टोरैंटों की साल 2020-21 के लिए अप्रैल से सितम्बर 2020 तक की सालाना लाइसेंस फीस और अप्रैल से जून और जुलाई से सितम्बर 2020 की तिमाही अनुमानित फीस माफ करने को मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 1 अप्रैल, 2020 से लेकर 30 सितम्बर, 2020 तक के समय के लिए होटलों और रैस्टोरैंटों के 1065 बारों की सालाना लाइसेंस फीस 50 प्रतिशत माफ किए जाने से खज़ाने पर 1355.50 लाख रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो कि 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व का आधा है। इसी तरह ही उपरोक्त समय के लिए कुल 2324 लाइसेंस प्राप्त मैरिज पैलेसों के सम्बन्ध में यह वित्तीय बोझ 350 लाख रुपए का होगा, जो कि साल 2020-21 के अनुमानित राजस्व का आधा हिस्सा होगा। जहाँ तक बारों के लाइसेंसों की आगामी तिमाही अनुमानित फीस माफ करने का सवाल है तो इसमें वित्तीय बोझ की कोई गुंजाईश नहीं है, क्योंकि फीस माफी का अनुमान सिर्फ़ अग्रिम तौर पर एकत्रित की गई फीस सम्बन्धी ही लगाया जा सकता है जो कि एडजस्ट होने योग्य है और अब फीस एकत्रित किए जाने को बारों द्वारा खरीद किए जाने तक आगे करने का प्रस्ताव है।

यह ध्यान देने योग्य है कि होटल एंड रैस्टोरैंट एसोसिएशन ऑफ पंजाब, होटल रैस्टोरैंट एंड रिजॉर्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब और मैरिज पेलेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब द्वारा मंत्रियों के समूह से लाइसेंस फीस और तिमाही अनुमानित फीस में छूट देने की माँग की गई थी, क्योंकि कोविड-19 महामारी और इसके बाद कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इस मसले को वित्त कमिश्नर (कर) ए. वेणू प्रसाद और आबकारी कमिश्नर रजत अग्रवाल के साथ विचारा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास मंज़ूरी के लिए भेजा गया।

जिला उद्योग केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में 1034 युवाओं को मिला रोजगार, 1172 युवाओं ने लिया भाग

23 कंपनियों ने रोजगार मेले में भाग लेकर युवाओं का नौकरी के लिए किया चयन

■ जालंधर/रवि

जिला रोजगार ब्यूरो में बुधवार को घर-घर रोजगार मुहिम के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जोकि छठे मैगा जॉब फेयर के तहत चल रहे रोजगार मेलों का हिस्सा था। रोजगार मेले में 1034 युवाओं का विभिन्न कंपनियों की तरफ से नौकरियों के लिए चयन किया गया। डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने बताया कि इस रोजगार मेले में 1172 बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा

लिया था, जिनका 23 विभिन्न कंपनियों की तरफ से चयन किया गया। इन कंपनियों में ए-वन इंटरनेशनल, गूगल पे, 9 टू 5 टैक्नोलॉजी, पुखराज हेल्थकेयर, कैपीटल अस्पताल शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन मेलों के जरिए रोजगार हासिल करने वाले युवा राज्य के आर्थिक-सामाजिक विकास में हिस्सेदार बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह की अगवाई में पंजाब सरकार की तरफ से आयोजित इस तरह के मेले युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार मेलों के दौरान कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार की तरफ से जारी सुरक्षा माणकों का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनना और हाथ धोने जैसी सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह डब्ल्यू. डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.जी.आर.के.ए.एम.कॉम पर भी खुद का पंजीकरण करवाएं और इसके अलावा वह किसी भी जानकारी के लिए 90569-20100 पर संपर्क कर सकते हैं।

बहुजन समाज फ्रंट पंजाब की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया

■ जालंधर/रवि

बहुजन समाज फ्रंट पंजाब की तरफ से डीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा की साल 2017 से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भारत सरकार की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम तहत राशि जारी की जाती रही है मगर पंजाब सरकार ने यह राशि कालेजों और यूनिवर्सिटयों को जारी नहीं की और पंजाब के 1650 कालेजों और यूनिवर्सिटयों की 13 एसोसिएशनों पर आधारित जत्थेबंदी जैक ने बठिंडा में मीटिंग कर मता पास किया की वह आगे से दलित समाज और कम गिनती समाज के 3 लाख विद्यार्थियों को दाखला नहीं

देंगे। कालेजों और यूनिवर्सिटयों का पंजाब सरकार की तरफ से 1850 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंजाब कांग्रेस सरकार दलित विरोधी है और वह अपनी नीतियों के तहत पंजाब के दलित समाज को पढ़ाई से दूर रखना चाहती है। इस स्थिति में दलित समाज अनपढ़ रह जाएगा।

पंजाब सरकार की दलित समाज प्रति गलत नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई। हम यह मांग करते है की साधू सिंह धर्मसोत को मंत्री मण्डल से तुरंत बाहर किया जाए और इस घपले की जाँच सी.बी.आई. से तुरंत करवाई जाए और बनती हुई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि को सरकार द्वारा जारी किया जाए। इस मौके पर मौजूद सुखविंदर सिंह कोटली, एस.पी सिंह गोराया, सुखवीर सिंह सलीमार, रमेश चोहका, जगदीश राणा, जस्सी प्रजापत, अमरजीत राम दासिया, रमन माही अंबेडकर टाइगर फोर्स, जस्सी तलन गुरु रविदास टाइगर फोर्स व अन्य शामिल थे।

खेलगतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 60 लाख रुपए की लागत से 11 मॉडल प्ले फील्ड के निर्माण कार्यों का 2 अक्तूबर होगा शिलान्यास

■ जालंधर/रवि

जिले में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 60 लाख रुपए की लागत से हरेक ब्लॉक में एक मॉडल प्लेग्राउंड तैयार किया जाएगा, जिसके निर्माण कार्य का उद्घाटन 2 अक्तूबर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शुरू करवाएंगे। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) जसबीर सिंह ने बुधवार को खेल स्टेडियम के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक में व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्यभर में ब्लॉक स्तर पर मॉडल प्लेग्राउंड तैयार करने का प्रोजेक्ट करवाएंगे शुरू

उन्होंने कहा कि जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मॉडल प्ले फील्ड तैयार करवाए जा रहे हैं, जिनमें वॉकिंग ट्रैक, सोलर लाइटें, एथलेटिक्स ट्रैक, कबड्डी व वॉलीबॉल मैदान इत्यादि तक की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि जिले में खेल गतिविधियों को उत्साहित करने व ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 11 प्ले फील्ड का उद्घाटन किया जा रहा है लेकिन हरेक ब्लॉक में 5-5 प्ले फील्ड बनाने का प्रस्ताव है। एडीसी ने बताया कि जिला स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इन खेल मैदानों के वर्चुअल उद्घाटन समारोह आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक आदमपुर, भोगपुर, जालंधर ईस्ट, जालंधर वेस्ट, लोहियां, महितपुर, नकोदर, नूरमहल, फिल्लौर, रुड़का कलां व शाहकोट में एक-एक खेल स्टेडियम तैयार किया जाएगा। एडीसी जसबीर सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत व लगन से निभाने के लिए कहा। इस मौके पर एसडीएम जयइंद्र सिंह, सहायक कमिश्नर हरदीप सिंह, डीईओ हरिंदरपाल सिंह, रामपाल व अन्य मौजूद थे।

कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटों में 17 वर्षीय लड़के के कत्ल केस की गुत्थी सुलझाई

■ जालंधर/रवि

सोमवार शाम को छावनी क्षेत्र के लाल कुरती मार्केट में हुए 17 वर्षीय लड़के के कत्ल की गुत्थी को कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटों में सुलझा लिया है। मंगलवार को इस केस में मृतक के नाबालिग दोस्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जानकारी देते पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कैंट पुलिस स्टेशन में अशोक कुमार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302, 34 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। अशोक कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका पोता अरमान छावनी में स्थानीय केवी-4 में 12वीं कक्षा में प ?ता था, जिस का पिता एनआरआई है जोकि फ्रांस में रहता है। जबकि

मृतक की मां अपनी बेटी के साथ हिमाचल प्रदेश गई हुई थी।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अशोक ने बताया कि जब वह सोमवार की शाम को अरमान को घर मिलने गया तो उसकी खून से लथपथ लाश देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे और सिर पर गहरी चोट थी। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने आगे बताया कि जानकारी मिलने पर डीसीपी बलकार सिंह, एडीसीपी अशवनी कुमार, एसीपी मेजर सिंह, एसीपी कंवलजीत सिंह, सीआईए के प्रमुख हरमिन्दर सिंह और अशवनी कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस केस में जांच के बाद एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, जोकि अरमान का दोस्त है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मृतक अरमान और आरोपी दोनों पहले इकठ्ठे पड़ते थे और मृतक की एक लड़की के साथ दोस्ती थी, वह भी नाबालिग है। उन्होनें बताया कि आरोपी भी उसी लड़की के प्रति भावनाओं रखता था, जिस कारण वह मृतक से ईष्या करने लगा। उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस बीच अरमान को मारने की साज़िश रची और योजनाबद्ध तरीके के साथ जुर्म को अंजाम दिया। आरोपी ने मृतक के सिर और चेहरे पर क्रिकेट बैट के साथ हमला किया और फिर उस का गला घोंट दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी को जुविनाईल कोर्ट में पेश किया जायेगा। उन्होंने 24 घंटों में कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस मुलाजिमों को उपयुक्त इनाम देने का ऐलान भी किया।

आईपीएल बड़ा ब्रांड है और मैं जानता हूं कि अगर हमारे खिलाड़ियों बाबर आजम और अन्य को इसमें खेलने का मौका मिलता है तो वे दबाव भरी परिस्थितियों में खेलना सीखते-शाहिद अफरीदी

SPORTS PLANET स्पोर्ट्स प्लैनट

लीवरपूल के मिडफील्डर थियागो अलकेंटरा कोरोना वायरस पॉजिटिव

■ लीवरपूल/ब्यूरो

लीवरपूल के मिडफील्डर थियागो अलकेंटरा कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इस महीने बायर्न म्यूनिख से इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन टीम से जुड़ने वाले अलकेंटरा नियमों के अनुसार अब कम से कम 10 दिन तक पृथकवास में रहेंगे।

स्पेन के इस 29 साल के खिलाड़ी ने चेल्सी के खिलाफ 2-0 की जीत के दौरान लीवरपूल की ओर से प्रीमियर लीग में पदार्पण किया था लेकिन सोमवार को आर्सेनल के खिलाफ 3-1 की जीत के दौरान नहीं खेल पाए। मंगलवार को जारी बयान में लीवरपूल ने हालांकि यह नहीं बताया कि उनका परीक्षण कब किया गया था। प्रीमियर लीग ने सोमवार को घोषणा की थी कि 10 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते हफ्ते 1595 खिलाड़ियों और क्लब के स्टाफ के सदस्यों का परीक्षण किया गया था। इसमें से तीन पॉजिटिव मामले वेस्ट हैम से जुड़े थे जिसमें मैनेजर डेविड मोयेस भी शामिल हैं।

कभी आई.पी.एल. टूर्नामेंट का हिस्सा रहे शाहिद अफरीदी को है इस बात का अफसोस

■ कराची/ब्यूरो

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को अफसोस है कि उनके टॉप खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे जिससे उन्हें काफी फायदा मिल सकता था। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबर के अनुसार अफरीदी ने कहा कि आईपीएल किसी भी खिलाड़ी के लिये अनुभव हासिल करने, प्रदर्शन में सुधार करने और 'एक्सपोजर' के लिये बड़ा मंच है। गौरतलब है कि अफरीदी साल 2008 में आईपीएल की टीम डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा थे।

उन्होंने कहा, 'आईपीएल बड़ा ब्रांड है और मैं जानता हूं कि अगर हमारे खिलाड़ियों बाबर आजम और अन्य को इसमें खेलने का मौका मिलता है तो वे दबाव भरी परिस्थितियों में खेलना सीखते। बदकिस्मती से मौजूदा नीतियों के कारण हमारे खिलाड़ियों को यह बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा।' इस पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईपीएल से अनुपस्थिति क्रिकेट के कारण नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमारे खिलाडियों की दुनिया भर की अन्य लीगों में मांग है और अच्छी चीज है कि उनके पास अपनी प्रतिभा दिखाने, अनुभव हासिल करने और टॉप खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए खुद की टॉप लीग (पाकिस्तान सुपर लीग) है।' पाकिस्तानी खिलाड़ी 2008 के आईपीएल सीजन के बाद से इस लीग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। अफरीदी ने माना कि उन्हें इतने सालों तक भारत में क्रिकेट फैंस से काफी समर्थन मिला है।

उन्होंने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि भारत में मैंने क्रिकेट का लुत्फ उठाया है और मुझे भारत के लोगों से काफी प्यार और सम्मान मिला है।

अब मैं सोशल मीडिया पर बात करता हूं तो मुझे भारत से काफी संदेश मिलते हैं और मैं कई लोगों को जवाब भी देता हूं। मेरा मानना है कि भारत का अभी तक का तजुर्बा शानदार रहा है।'

डीसी ने नई अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद प्रबंधों का लिया जायजा

पंजाब सरकार धान की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध : घनश्याम थोरी

■ जालंधर/रवि

डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने कहा है कि पंजाब सरकार किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा सीजन में धान की सुचारू और निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है।

बुधवार को शहर की नई अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार की तरफ से धान के एक-एक दाने की निर्विघ्न खरीद व लिफ्टिंग की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से अनाज मंडियों में से किसानों की फसल की सुचारू और निर्विघ्न ढंग के साथ लिफ्टिंग को यकीनी बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं। थोरी ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आने दी जायेगी।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि खरीद के अलावा अनाज की ढुलाई और भंडारण के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियां संबंधित एजेंसियों को खरीद के अलॉट किये गए शेयर मुताबिक धान की खरीद करें व साथ-साथ लिफ्टिंग सुनिश्चित करें। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि प्रत्येक खरीद केंद्र में आधिकारियों को बिजली, किसानों के लिए शैड्स, पीने वाले पानी की स्पलाई और गेहूं की गुणवत्ता की जांच के लिए आवश्यक उपकरणों समेत तमाम जरुरी प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधिकारियों को पंजाब सरकार की तरफ से जारी

सुरक्षा सावधानियों का प्रमुखता से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरी खरीद प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अब तक 9396 मीट्रिक टन धान की आमद मंडियों में हो चुकी है, जिस में से खरीद एजेंसियाँ की तरफ से 8834 मीटरिक टन की खरीद की गई है। जिले में धान की खरीद व लिफ्टिंग के लिए 149 मंडियां-खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें खरीद में कोई दिक्कत आती है तो वह प्रशासन की तरफ से स्थापित कंट्रोल रूम नंबर 01815019252 पर संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर एसडीएम राहुल सिंधू, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर नरिंदर सिंह, जिला मंडी अधिकारी मुकेश कैले व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

श्री गुरू तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर हर गांव में 400 पौधे लगाने की मुहिम की शुरू

■ चंडीगढ़ / एस.ए.एस.नगर/ब्यूरो

71वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाने सम्बन्धी आज मुल्लांपुर जंगल में पौधे लगाए गए। वन और वन्य जीव सुरक्षा मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने इस समागम की अध्यक्षता की। इस मौके पर श्री गुरु तेग़ बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित हर गाँव में 400 पौधे लगाने की मुहिम भी शुरू की गई। इस मौके पर संबोधन करते हुये वन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पंजाब की हिदायतों के अनुसार श्री गुरु तेग़ बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए हर गाँव में 400 पौधे लगाए जाएंगे। ग्रीनिंग पंजाब मिशन के तहत यह मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के अंतर्गत पंजाब रा%य के कुल 12986 गाँवों में लगभग 52 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। मुल्लांपुर वन क्षेत्र में 'नगर वन' स्थापित करने के काम की शुरूआत करते हुये उन्होंने बताया कि इसको 37 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग को गमाडा ने मुल्लांपुर-सिसवां सड़क के निर्माण के लिए विभाग की तरफ से दी ज़मीन के बदले उक्त ज़मीन दी गई थी। इस ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा बंजर था परन्तु विभाग के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप कई किस्मों के पौधे लगाने की कोशिश और जांच की गई और अंत में इस क्षेत्र को 'नगर वन' के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके चारों तरफ़ कँटीली तार लगाई जायेगी और वन में से निकलने के लिए रास्ते बनाऐ जाएंगे जिससे लोग इस क्षेत्र का दौरा कर सकें और वन की सुंदरता का आनंद का लुफ्त ले सकें। यह क्षेत्र लोगों को ताजी और शुद्ध हवा मुहैया करवाने में सहायक सिद्ध होगा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.